

बोलने वाला हूँ। महोदय, कोंकण क्षेत्र में उत्पादित होने वाला हापुस आम, मतलब अल्फांसो मैंगो अपने मधुर रस, उत्तम स्वाद, सुनहरे रंग और तंतु विरत पल्प के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। हापुस आम की यह गुणवत्ता विशेष कोंकण की रासायनिक और भौतिक गुणवत्तापूर्ण माटी, पानी और हवा के कारण आती है। इसका मतलब यह है कि अगर यही हापुस के पेड़ कोंकण व्यतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में लगाए जाएं, तो उसमें आने वाला फल इतना गुणवत्तापूर्ण नहीं रहेगा। इसलिए कई रिसर्च और इंवेस्टीगेशन के बाद जियोलॉजिकल इंडिकेटर अधिनियम, 1999 द्वारा जीआई रजिस्ट्री चेन्नई द्वारा महाराष्ट्र कोंकण के पांच जिले, जिनमें रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, थाना और पालघर में पैदा होने वाला या इसमें हापुस के पेड़ को लगाने वाला फल, मतलब आम ही हापुस माना जाएगा, ऐसा माना जाता है। इसका मतलब यह है कि अन्य क्षेत्र में लगाये गये हापुस जैसे पेड़ से आने वाला आम हापुस नहीं माना जाएगा।

सर, जैसे लंगड़ा आम उत्तर प्रदेश का रहता है, उसे जीआई मानक मिला है। मालदा, पश्चिम बंगाल का होता है। इसका मतलब यह है कि अगर महाराष्ट्र में या कोंकण में लंगड़ा आम का पेड़ लगाया जाए या मालदा आम का पेड़ लगाया जाए, तो उससे होने वाला फल मालदा या लंगड़ा नहीं माना जाएगा। जीआई authentication के कई फायदे हैं। ग्राहक को गुणवत्तापूर्ण authentic उत्पाद मिलता है। किसानों को आर्थिक फायदा होता है, पारंपरिक विरासत का संरक्षण होता है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने माल की पहचान रहती है। सर, अभी आम का सीजन चालू है। बाजार में कोंकण का हापुस जितना आता है, उससे तीन गुना हापुस बताकर मार्किट में बेचा जाता है। एक हापुस के पीछे दो आम बनावट हापुस बेचे जाते हैं। इससे ग्राहक को नुकसान होता है, किसानों को नुकसान होता है और ब्रैंडिंग नहीं हो पाती है। अगर ऐसे ही चलता रहेगा, तो हापुस की गुणवत्ता की कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में यह विरासत नष्ट हो जाएगी।

महोदय, मेरी यह मांग है कि कोंकण के बाहर से आने वाला हापुस आम कई एपीएमसी और व्यापारियों द्वारा खरीदा और बेचा जाता है। इस तरीके का व्यवहार, जीआई टैग अधिनियम, 1999 द्वारा गैर-कानूनी मांग के गैर-व्यवहार करने वालों को दंडित किया जाए और कोंकण की इस विरासत को संरक्षित किया जाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Dhairyashil Mohan Patil: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Shri Saket Gokhale (West Bengal), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri Samik Bhattacharya (West Bengal), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shri Madan Rathore (Rajasthan) and Shri Niranjana Bishi (Odisha).

Shri Ritabrata Banerjee; Demand for Strict Action against Provident Fund defaulters.

Demand for strict action against Provident Fund defaulters

SHRI RITABRATA BANERJEE (West Bengal): Sir, the Employees Provident Funds

and Miscellaneous Provisions Act, 1952, is one of the most important social security schemes for the benefit of the working people of our country. This Act provides for the institution of provident funds, pension funds and deposit-linked insurance funds for employees in factories and other establishments.

Provident Fund is a Central Government-managed retirement savings scheme where both employees and employers contribute a portion of the employee's salary to create a fund for retirement or emergencies, managed by organisations like the Employees Provident Fund Organisation. Sir, unfortunately enough, defaults under the EPFO has reached a record high of almost Rs. 26,000 crore at the end of 2023-24, marking an increase of 69.3 per cent from Rs. 15,254 crore the previous year, according to official data. The private sector's default on provident fund deposits with EPFO has been constantly on the rise in the last five years in an alarming rate. In the private sector particularly, a large number of employers not only are not depositing their contributions but are also not depositing the contribution of the employee which the employers are deducting from salaries. This is a dangerous and alarming trend. In order to ensure stringent measures against the PF defaulters, the concerned State Government must have the concrete PF data from the PF offices which are not happening in reality.

The Labour Department of the Government of West Bengal has been repeatedly requesting the Additional Central PF Commissioner, *in-charge* of West Bengal, Sikkim and Andaman & Nicobar Islands to share the list of defaulters of jute mills since 2024. The concerned Additional Central PF Commissioner has not bothered to give any details till date. There was a written complaint to the Labour Minister, West Bengal against a private contractor agency, working at Haldia Dock Complex, by nearly 1,000 contractual employees of Haldia port regarding huge PF default. The Labour Department has been sending formal letters to the same Additional Central PF Commissioner since August 2023 but till date no concrete reply has been received. Naturally, a suspicion of an unholy nexus between the said office and the contractor arises. The question is whether this particular office situated in DK Block, Sector II, Salt Lake, West Bengal, is trying to protect that particular PF defaulter at any cost. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seat.

SHRI RITABRATA BANERJEE: Similarly, since 2024, the West Bengal Labour Department has been writing to the Regional Provident Fund Commissioners of

Jalpaiguri, Siliguri and Darjeeling requesting for the garden-wise PF dues under their jurisdiction. Unfortunately enough, no concrete reply has been received from them.

In order to ensure stringent action against PF defaulters, through you, I would request you.....(*Time-bell rings.*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over. The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Ritabrata Banerjee: Shri Jose K. Mani (Kerala), Shri M. Shanmugam (Tamil Nadu), Ms. Dola Sen (West Bengal), Shrimati Sagarika Ghose (West Bengal), Shri Mohammed Nadimul Haque (West Bengal), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Ms. Sushmita Dev (West Bengal), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Shri Saket Gokhale (West Bengal), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri A. A. Rahim (Kerala), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu) and Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu).

Shrimati Darshana Singh, "Demand for mandatory provisions of First Aid training for teachers and students in the schools."

Demand for mandatory provisions of First Aid training for teachers and students in the schools

श्रीमती दर्शना सिंह (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आज शून्य काल में विद्यालयों में प्राथमिक उपचार, यानी कि फर्स्ट एड का प्रशिक्षण देने हेतु विषय पर अपनी बात रखना चाहती हूँ।

माननीय उपसभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से आपका ध्यान विद्यालयों में प्राथमिक उपचार, यानी कि फर्स्ट एड की शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता की ओर आकर्षित कराना चाहती हूँ। स्कूलों में अक्सर बच्चों के साथ कई प्रकार की दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिनमें चोट लगना, जलना, साँप या अन्य जीव जंतुओं के काटने की घटनाएं प्रमुख हैं। इन आपातकालीन स्थितियों में सही समय पर दिया गया प्राथमिक उपचार जीवन को बचा सकता है। अतः इस तरह की दुर्घटनाओं से जान-माल की रक्षा करने के लिए स्कूलों में शिक्षकों एवं बच्चों, दोनों के लिए प्राथमिक उपचार के प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे ऐसी दुर्घटनाओं से होने वाली जान-माल की हानि को कम किया जा सके।

महोदय, इस प्रशिक्षण में उन्हें दुर्घटनाओं से बचाव के तरीके, प्राथमिक उपचार से संबंधित सभी तकनीकी जानकारियाँ, जैसे जानवरों के काटने पर उपचार, सीपीआर और अन्य जीवन रक्षक तकनीकें सिखाई जाएं। यह प्रशिक्षण शिक्षकों और बच्चों को न केवल स्कूल परिसर के अंदर आपातकालीन स्थितियों में मददगार बनाएगा, बल्कि इस प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षक और बच्चे स्कूल के बाहर भी परिवार और आस-पड़ोस में होने वाली घटनाओं में मदद कर पाएंगे।